# Deregulation Phase-1 and Ease of Doing Business in Rajasthan

Rajasthan has made substantial strides during the 'Deregulation Phase-1', which has enhanced its appeal to investors. The Deregulation Cell of the Chief Secretary's Office has prepared a progress report for the month of April 2026 in which 9,010 applications were received and 6,103 were approved on the Raj Nivesh Portal. During the month, the state approval rate was 67.7 percent. The initiative is supporting the vision of Viksit Rajasthan and Rising Rajasthan by making the processes simpler, ensuring timely disposal of applications and encouraging decentralised implementation in districts.

## Key points from the Monthly Progress Report:

- In April 2026, 6,103 applications were approved in the Raj Nivesh Portal, which received 9,010 applications in Rajasthan.
- Overall, the state's approval rate was 67.7 percent.
- Jaipur was the top district with 1,932 applications and 1,351 approvals.
- Kota's approval rate was almost 83.8 percent.
- Hanumangarh had an approval percentage of almost 82.5 percent.
- Baran, Bhilwara, Chittorgarh, Tonk, Udaipur and Jalore had a higher approval rate of above 70 per cent.
- The Deregulation Cell established under the Chief Secretary Office is closely tracking the progress of investments per month.

## District-Level Performance

### Leading District

- In April 2026, Jaipur district was the topper among all districts.
- 1,932 applications were received by the district and were approved 1,351.
- It has captured the attention for the role played by the major urban and industrial hubs in Rajasthan's investment ecosystem.

### Other Active Districts

- Other cities where there was significant participation in the Raj Nivesh Portal were Jodhpur, Sikar, Ajmer, Bikaner, Kota, Hanumangarh, Alwar, Churu and Bhilwara.
- High approval rates in Kota and Hanumangarh are indicative of efficient administration and speedy service delivery.
- Districts with high approval rate (>70 percent) signify improved decentralised governance and investment facilitation.

### The following emerging sectors have caught the eye of investors:

- Investor appetite is growing in the emerging fields like Ayush, agro processing, defence and education.
- The highest level of proposed investment was on tourism and hospitality.
- The contributions of the tourism and hospitality proposals from Jaipur, Udaipur, Pali, Rajsamand, Sikar and other districts were significant.
- The engineering investment interest was shown in Alwar and Kotputli-Behror.
- The renewable energy initiatives came from various districts.
- Interest in investing in waste management was seen in Ajmer and Bhilwara.
- Jodhpur was the hallmark of textile-investment interest.

## Objectives and Benefits

### Objectives

- Make the process of approving investors easier.
- Make sure that applications are disposed of within a timeframe.
- Facilitate ease of doing business in Rajasthan.
- Improve inter-departmental and inter-district cooperation.
- Encourage investment away from leading urban areas.

### Benefits

- Increases the image of Rajasthan as an investment destination of choice.
- Promotes investment in the traditional and new sectors.
- Supports economic development that is decentralised.
- Improves management and service.

RASonly

- Promotes the larger goals of Viksit Rajasthan and Rising Rajasthan.

## Conclusion

Rajasthan's progress under Deregulation Phase-1 is impressive with a strong thrust towards investor friendly governance. The state's push towards a more efficient and diversified investment ecosystem can be seen from the faster approvals via Raj Nivesh, monitoring at the district level, as well as increased interest among investors in sectors such as tourism, Ayush, agro-processing, defence, renewable energy and education.

## MCQs

1.In Deregulation Phase-1, how many applications were approved on the Raj Nivesh Portal in April 2026?

(a) 1,351

(b) 6,103

(c) 9,010

(d) 83.8 percent

Answer: (b) 6,103

Explanation : According to the information provided, the number of applications received in the Rajasthan for investment through the Raj Nivesh Portal in April 2026 is 9010. Of these, 67.7 percent or 6,103 were approved. This is in line with the state's initiatives to streamline processes and make doing business easier as part of Deregulation Phase-1.

2. Which District had the highest number of approvals in the progress report April 2026?

(a) Kota

(b) Hanumangarh

(c) Jaipur

(d) Jodhpur

Answer: (c) Jaipur

Explanation: Jaipur was the top district to come out with the April 2026 Progress Report. It got 1,932 applications and accepted 1,351 applications on "Raj Nivesh Portal". This resulted in a total approvals jump of Jaipur district in Deregulation Phase-1.

RASonly

3. What is the maximum proposed investment in Rajasthan in April 2026 in which sector?

(a) Tourism & Hospitality

(b) Textile

(c) Waste management

(d) Engineering

Answer: (a) Tourism and hospitality

Explanation : The report indicates that the tourism and hospitality sector had the largest recommended investment in April 2026. The areas of contribution were Jaipur, Udaipur, Pali, Rajsamand, Sikar etc. Other industries—like engineering, renewable energy, waste management and textiles—also expressed an interest in investment.

## विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 और राजस्थान में व्यवसाय सुगमता

राजस्थान ने **विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1** के तहत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, जिससे राज्य की निवेश-अनुकूल छवि मजबूत हुई है। मुख्य सचिव कार्यालय के अंतर्गत गठित विनियमन-शिथिलीकरण प्रकोष्ठ द्वारा तैयार अप्रैल 2026 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, राज निवेश पोर्टल पर 9,010 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,103 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इस अवधि में राज्य की स्वीकृति दर 67.7 प्रतिशत रही। यह पहल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर और जिलों में विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयन को बढ़ावा देकर **विकसित राजस्थान** और **राइजिंग राजस्थान** की परिकल्पना को आगे बढ़ा रही है।

**मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु**

- अप्रैल 2026 में राजस्थान में राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9,010 आवेदनों में से 6,103 आवेदनों को स्वीकृति दी गई।
- राज्य की कुल स्वीकृति दर 67.7 प्रतिशत रही।
- जयपुर 1,932 आवेदनों और 1,351 स्वीकृतियों के साथ अग्रणी जिला रहा।
- कोटा में स्वीकृति दर लगभग 83.8 प्रतिशत रही।
- हनुमानगढ़ में स्वीकृति दर लगभग 82.5 प्रतिशत रही।
- बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, उदयपुर और जालोर में 70 प्रतिशत से अधिक स्वीकृति दर दर्ज की गई।
- मुख्य सचिव कार्यालय के अंतर्गत गठित विनियमन-शिथिलीकरण प्रकोष्ठ निवेश से जुड़ी मासिक प्रगति की सघन निगरानी कर रहा है।

RASonly

## जिला-स्तरीय प्रदर्शन

### अग्रणी जिला

- अप्रैल 2026 में जयपुर सभी जिलों में सबसे आगे रहा।
- जिले में 1,932 आवेदन प्राप्त हुए और 1,351 आवेदनों को स्वीकृति दी गई।
- यह प्रदर्शन राजस्थान के निवेश तंत्र में प्रमुख शहरी और औद्योगिक केंद्रों की भूमिका को दर्शाता है।

### अन्य सक्रिय जिले

- जोधपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू और भीलवाड़ा ने भी राज निवेश पोर्टल पर उल्लेखनीय सहभागिता दर्ज की।
- कोटा और हनुमानगढ़ की उच्च स्वीकृति दर बेहतर प्रशासनिक दक्षता और तेज सेवा वितरण को दर्शाती है।
- 70 प्रतिशत से अधिक स्वीकृति दर वाले जिले विकेन्द्रीकृत शासन और निवेश सुविधा में सुधार का संकेत देते हैं।

### निवेशकों की रुचि वाले उभरते क्षेत्र

- आयुष, कृषि-प्रसंस्करण, रक्षा और शिक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है।
- पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्तावित निवेश दर्ज किया गया।
- जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सीकर और अन्य जिलों ने पर्यटन एवं आतिथ्य प्रस्तावों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में अभियांत्रिकी क्षेत्र में निवेश रुचि दिखाई दी।
- विभिन्न जिलों से नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए।
- अजमेर और भीलवाड़ा में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में निवेश रुचि दिखाई दी।
- जोधपुर में वस्त्र क्षेत्र से संबंधित निवेश रुचि परिलक्षित हुई।

## उद्देश्य और लाभ

### उद्देश्य

- निवेशकों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाना।
- आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना।
- राजस्थान में व्यवसाय सुगमता को बढ़ाना।
- विभागों और जिलों के बीच समन्वय को मजबूत करना।
- प्रमुख शहरी केंद्रों से आगे भी निवेश को बढ़ावा देना।

RASonly

### लाभ

- राजस्थान की छवि एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में मजबूत होती है।
- पारंपरिक और नए क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
- विकेन्द्रीकृत आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है।
- प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण में सुधार होता है।
- विकसित राजस्थान और राइजिंग राजस्थान के व्यापक लक्ष्यों को बढ़ावा मिलता है।

## निष्कर्ष

विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 के तहत राजस्थान का प्रदर्शन निवेश-अनुकूल शासन की दिशा में मजबूत प्रयास को दर्शाता है। राज निवेश पोर्टल के माध्यम से तेज स्वीकृतियां, जिला-स्तरीय निगरानी और पर्यटन, आयुष, कृषि-प्रसंस्करण, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेशकों की बढ़ती रुचि राज्य को अधिक दक्ष और विविध निवेश तंत्र की ओर आगे बढ़ा रही है।

## बहुविकल्पीय प्रश्न

**1. विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 के तहत अप्रैल 2026 में राज निवेश पोर्टल पर कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई?**

(a) 1,351
(b) 6,103
(c) 9,010
(d) 83.8 प्रतिशत

**उत्तर: (b) 6,103**

**व्याख्या:** अप्रैल 2026 में राजस्थान में राज निवेश पोर्टल पर 9,010 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 6,103 आवेदनों को स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य की कुल स्वीकृति दर 67.7 प्रतिशत रही। यह विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यवसाय सुगमता को बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।

**2. अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृतियों के मामले में कौन-सा जिला अग्रणी रहा?**

(a) कोटा
(b) हनुमानगढ़
(c) जयपुर
(d) जोधपुर

**उत्तर: (c) जयपुर**

**व्याख्या:** अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जयपुर स्वीकृतियों के मामले में अग्रणी जिला रहा। जयपुर में राज निवेश पोर्टल पर 1,932 आवेदन प्राप्त हुए और 1,351 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इस कारण विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 के तहत कुल स्वीकृतियों के आधार पर जयपुर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला रहा।

RASonly

**3. अप्रैल 2026 में राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्तावित निवेश दर्ज किया गया?**

(a) पर्यटन और आतिथ्य
(b) वस्त्र
(c) अपशिष्ट प्रबंधन
(d) अभियांत्रिकी

**उत्तर: (a) पर्यटन और आतिथ्य**

**व्याख्या:** रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्तावित निवेश दर्ज किया गया। जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सीकर और अन्य जिलों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही अभियांत्रिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और वस्त्र क्षेत्रों में भी निवेश रुचि दिखाई दी।

# Viksit Bharat Vibrant Village Programme and Youth Participation in Nation Building

The team of 15 talented MY Bharat volunteers of Rajasthan has been selected for the Viksit Bharat Vibrant Village Programme to visit the border villages of Himachal Pradesh to gain insights into nation building, border life and community service. Chief Minister Bhajanlal Sharma congratulated the selected volunteers and said that it would help in developing patriotism, leadership and social responsibility among the youth. The programme is under the joint initiative of the Ministry of Youth Affairs and Sports and the Ministry of Home Affairs, Government of India. The volunteers of

Rajasthan are a part of a youth group of 100 members chosen from throughout the nation.

## Key Highlights of the Programme are the following:

- 15 brilliant volunteers from Rajasthan have been chosen for the programme.
- The chosen volunteers come from a 100-member youth group from all over India.
- Over 16 thousand young people from Rajasthan took part in the selection process.
- 2.59 lakh youth took part in the national quiz across the country.
- The volunteers will conduct visits to 20 identified border villages of HP.
- Youth will gain knowledge about the challenges in the border, life, culture, and developmental needs in the border area.
- Rajasthan's volunteers will also be a symbol of rich folk culture, traditions and life values of the state.

## Selections Through National level Quiz

### Viksit Bharat Vibrant Village Quiz

- The volunteers were chosen in a difficult national level competition.
- The Ministry of Youth Affairs and Sports hosted the Vibrant Village Quiz organized by MY Bharat on the MY Bharat Portal.
- The quiz was attended by a total of 2.59 lakh youths from all over the country.
- Over 16,000 youngsters from Rajasthan participated & acquitted themselves well.
- Top 15 youth from Rajasthan got the chance to participate in this historic programme.

## Learning in Border Villages

### This day is dedicated to orientation at Reckong Peo Base Camp.

- The programme will start in Reckong Peo on 3 June 2026 in base camp.
- The orientation process will continue till 5 June 2026.
- During this orientation the volunteers will be prepared for difficult geographical and climatic conditions.

### The Village Stay runs from 6th June to 12th June.

- The volunteers will remain in 20 identified border villages of H.P from 6th June to 12th June, 2026.
- They will have first-hand contact with the local villagers.
- By them, they will know about the social, cultural and developmental situations in border regions.

RASonly

- They will get into the discipline, spirit of National service of the Indo-Tibetan Border Police.

### Importance for Rajasthan

- The chosen youngster will be a representative of rich folk culture, traditions and social values of Rajasthan.
- Once back, they can share their experience for social awareness of youth participation in Rajasthan.
- They could inspire more youths to participate in nation building through their exposure to border areas.
- The programme builds the connection between youth leadership, national security awareness and grass roots development.
- It also gives emphasis upon the concept of youth at the centre of a developed India.

## Objectives and Benefits

### Objectives

- Engage young people in nation building process.
- Guide young volunteer groups to the understanding of life in the border villages.
- Raise awareness about the border challenges and its development needs.
- Promote service, respect and social responsibility.
- Engage youth with communities in strategic border areas.

### Benefits

- Enhances patriotic and leadership qualities among youth.
- Promotes cultural interaction between Rajasthan and HP.
- Develops knowledge about border area development.
- Encourages positive responsible citizenship.
- Supports the bigger vision of Viksit Bharat by involving youth.

## Conclusion

It is a significant opportunity for youth-led nationally (Youth Nation Building) under Viksit Bharat Vibrant Village Programme in Rajasthan with 15 MY Volunteers. The volunteers would get hands-on experience about border life, service, culture and development through orientation, village stay, interaction with the local communities and experience with Indo-Tibetan Border Police. This experience can subsequently help to spread their awareness and participation in youth activities in Rajasthan.

RASonly

## MCQs

1.What is the number of MY Bharat volunteers selected from Rajasthan for the programme of Viksit Bharat Vibrant Village?

(a) 20

(b) 100

(c) 15

(d) 2.59 lakh

Answer: (c) 15

Explanation : There are 15 talented MY Bharat volunteers from Rajasthan, who have been selected for Viksit Bharat Vibrant Village Programme. They are a part of a youth group of 100 members from all parts of India. These volunteers will go to the villages on the border of HP and engage in nation building and public awareness activities.

2. Which of the following ministries are organizing Viksit Bharat Vibrant Village Programme?

a) Ministry of Culture and Ministry of Tourism
(b) Ministry of Youth Affairs and Sports and Ministry of Home Affairs
(c) Ministry of Education and Ministry of Defence
(d) Ministry of Rural Development and Ministry of Panchayati Raj

Answer: b) Ministry of Youth Affairs and Sports and Ministry of Home Affairs

Explanation: The programme is being organised jointly by the Ministry of Youth Affairs and Sports and the Ministry of Home Affairs, Government of India. It aims to bring the youth in contact with border villages, sensitise them about issues on the border and motivate them in nation-building activities, service and public awareness programmes.

3. Where will the chosen volunteers be accommodated during the programme (3 June – 12 June 2026)?

(a) 20 identified border villages of Himachal Pradesh
(b) Jaipur district headquarters
(c) 15 villages of Rajasthan
(d) Reckong Peo base camp only

Answer: (a) 20 villages have been identified on the border of HP.

Explanation: The selected MY Bharat volunteers will be stationed in 20 border villages of HP from 6 June to 12 June 2026 after conducting an orientation process

RASonly

from 3 June to 5 June 2026 in the Reckong Peo base camp. They will meet local people and gain an understanding of social, cultural and developmental issues during this stay.

# विकसित भारत जीवंत ग्राम कार्यक्रम और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी

राजस्थान के 15 प्रतिभाशाली **माय भारत स्वयंसेवकों** का चयन **विकसित भारत जीवंत ग्राम कार्यक्रम** के लिए किया गया है। ये स्वयंसेवक हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में जाकर राष्ट्र निर्माण, सीमावर्ती जीवन और सामुदायिक सेवा को समझेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चयनित स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अनुभव युवाओं में देशभक्ति, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करेगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान के स्वयंसेवक देशभर से चयनित 100 युवाओं के दल का हिस्सा हैं।

## कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु

- राजस्थान से 15 प्रतिभाशाली स्वयंसेवकों का चयन किया गया है।
- चयनित स्वयंसेवक देशभर से चुने गए 100 युवाओं के दल का हिस्सा हैं।
- राजस्थान के 16 हजार से अधिक युवाओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया।
- देशभर से 2.59 लाख युवाओं ने राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी में भाग लिया।
- स्वयंसेवक हिमाचल प्रदेश के 20 चिन्हित सीमावर्ती गांवों का भ्रमण करेंगे।
- युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों, जनजीवन, संस्कृति और विकास की आवश्यकताओं को समझने का अवसर मिलेगा।
- राजस्थान के स्वयंसेवक राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

## राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी से चयन

### विकसित भारत जीवंत ग्राम प्रश्नोत्तरी

- स्वयंसेवकों का चयन कठिन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया।
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत द्वारा माय भारत पोर्टल पर **विकसित भारत जीवंत ग्राम प्रश्नोत्तरी** आयोजित की गई।
- इस प्रश्नोत्तरी में देशभर से कुल 2.59 लाख युवाओं ने भाग लिया।
- राजस्थान के 16 हजार से अधिक युवाओं ने इसमें भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन किया।
- राजस्थान के शीर्ष 15 युवाओं को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला।

RASonly

# सीमावर्ती गांवों में सीखने का अवसर

## रिकांगपिओ आधार शिविर में अनुकूलन

- कार्यक्रम 3 जून 2026 से रिकांगपिओ आधार शिविर में शुरू होगा।
- अनुकूलन प्रक्रिया 5 जून 2026 तक जारी रहेगी।
- इस अनुकूलन से स्वयंसेवकों को कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाएगा।

## 6 जून से 12 जून तक गांवों में प्रवास

- 6 जून से 12 जून 2026 तक स्वयंसेवक हिमाचल प्रदेश के 20 चिन्हित सीमावर्ती गांवों में प्रवास करेंगे।
- वे स्थानीय ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे।
- वे सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक परिस्थितियों को समझेंगे।
- वे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना को निकट से अनुभव करेंगे।

## राजस्थान के लिए महत्व

- चयनित युवा राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- लौटने के बाद वे अपने अनुभवों का उपयोग राजस्थान में सामाजिक जागरूकता और युवा सहभागिता बढ़ाने में कर सकेंगे।
- सीमावर्ती क्षेत्रों का अनुभव अधिक युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित कर सकता है।
- यह कार्यक्रम युवा नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता और जमीनी विकास के बीच संबंध को मजबूत करता है।
- यह विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका को भी रेखांकित करता है।

# उद्देश्य और लाभ

## उद्देश्य

- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- युवा स्वयंसेवकों को सीमावर्ती गांवों के जीवन से परिचित कराना।
- सीमावर्ती चुनौतियों और विकास की आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करना।
- सामरिक महत्व वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना।

RASonly

### लाभ

- युवाओं में देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है।
- राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा मिलता है।
- सीमावर्ती क्षेत्र विकास की समझ विकसित होती है।
- सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहन मिलता है।
- युवा भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य को समर्थन मिलता है।

## निष्कर्ष

विकसित भारत जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 15 माय भारत स्वयंसेवकों का चयन युवा-नेतृत्व वाले राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अनुकूलन, गांवों में प्रवास, स्थानीय समुदायों से संवाद और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के अनुभव के माध्यम से स्वयंसेवकों को सीमावर्ती जीवन, सेवा, संस्कृति और विकास की व्यावहारिक समझ मिलेगी। यह अनुभव आगे चलकर राजस्थान में सामाजिक जागरूकता और युवा सहभागिता को मजबूत कर सकता है।

## बहुविकल्पीय प्रश्न

**1. विकसित भारत जीवंत ग्राम कार्यक्रम के लिए राजस्थान से कितने माय भारत स्वयंसेवकों का चयन किया गया है?**

(a) 20
(b) 100
(c) 15
(d) 2.59 लाख

**उत्तर: (c) 15**

**व्याख्या:** विकसित भारत जीवंत ग्राम कार्यक्रम के लिए राजस्थान से 15 प्रतिभाशाली माय भारत स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। ये स्वयंसेवक देशभर से चयनित 100 युवाओं के दल का हिस्सा हैं। वे हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में जाकर राष्ट्र निर्माण और जनजागरूकता से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेंगे।

**2. विकसित भारत जीवंत ग्राम कार्यक्रम किन मंत्रालयों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है?**

(a) संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय
(b) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय
(c) शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय
(d) ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय

**उत्तर: (b) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय**

**व्याख्या:** विकसित भारत जीवंत ग्राम कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य

RASonly

युवाओं को सीमावर्ती गांवों से जोड़ना, सीमावर्ती चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण, सेवा तथा जनजागरूकता गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है।

**3. 6 जून से 12 जून 2026 तक चयनित स्वयंसेवक कहां प्रवास करेंगे?**

(a) हिमाचल प्रदेश के 20 चिन्हित सीमावर्ती गांवों में
(b) जयपुर जिला मुख्यालय में
(c) राजस्थान के 15 गांवों में
(d) केवल रिकांगपिओ आधार शिविर में

**उत्तर: (a) हिमाचल प्रदेश के 20 चिन्हित सीमावर्ती गांवों में**

**व्याख्या:** रिकांगपिओ आधार शिविर में 3 जून से 5 जून 2026 तक अनुकूलन प्रक्रिया पूरी करने के बाद चयनित माय भारत स्वयंसेवक 6 जून से 12 जून 2026 तक हिमाचल प्रदेश के 20 चिन्हित सीमावर्ती गांवों में प्रवास करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकासात्मक परिस्थितियों को समझेंगे।

RASonly

# Dairy Sector and Livelihood Security in Rajasthan

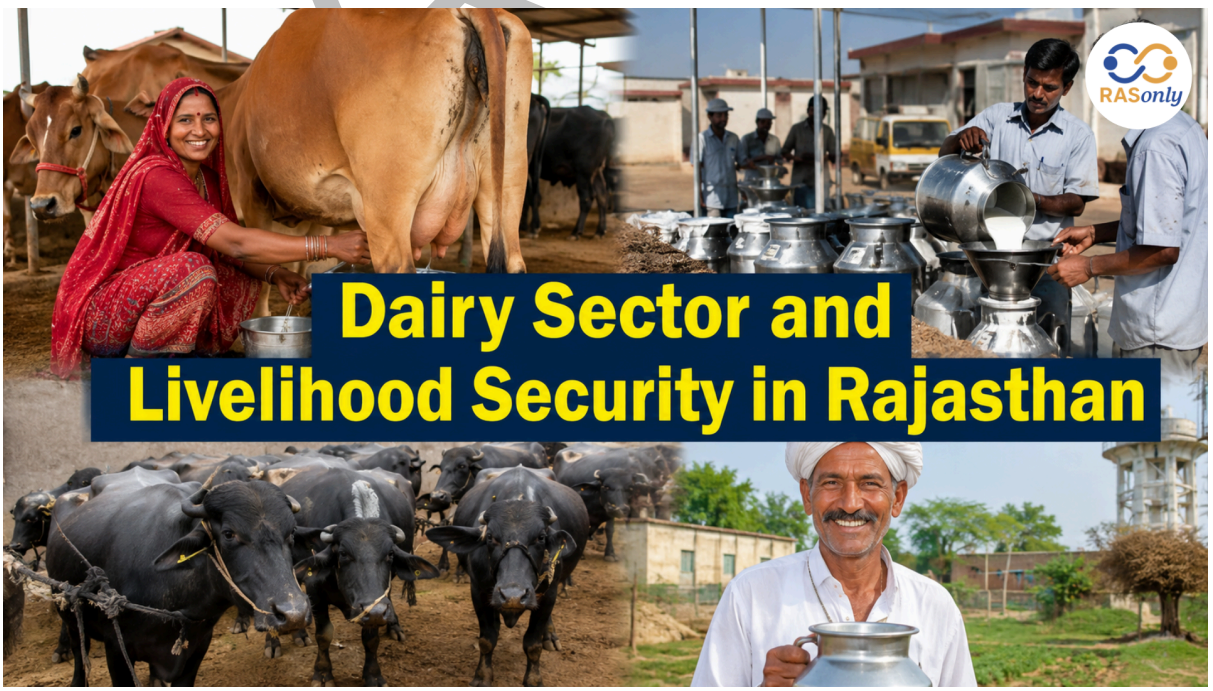

In India, the second largest milk producer state is Rajasthan and among the various livelihood supports for farmers, dairy is one of the strong ones. Dairy generates income on a daily basis for rural households, whereas crop income is one or two times per year. The total milk production in India was 247.87 million tonnes, with Rajasthan contributing 14.82 percent in terms of basic animal husbandry statistics 2025. This translates to almost one in every seven litres of milk being produced in India in Rajasthan. The production of milk has increased significantly in the state from nearly 77 lakh tonnes in 2001-02 to nearly 367 lakh tonnes in 2024-25.

## Key Highlights

- Rajasthan is now the second highest milk production state in India.
- The state accounts for 14.82 per cent of the total milk production in India.
- According to Basic Animal Husbandry Statistics 2025, India's milk production amounted to 247.87 million tonnes.
- The milk production in Rajasthan has risen from approximately 77 lakh tonnes in 2001-02 to almost 367 lakh tonnes in 2024-25.
- Rural families now derive a consistent income and economic means from dairy.
- Now the dairy industry in Rajasthan is not only concentrating its attention on production, but also processing.
- The total business of RCDF and district milk unions was almost about ₹10,500 crore in 2025–26.
- The state government has sanctioned a special fund of ₹2000 crore for the development of the dairy infrastructure.

## The states producing the majority of milk in India are given below:

### Top Milk-Producing States in India

| State | Share in India's Milk Production |
|---|---|
| Uttar Pradesh | 15.66% |
| Rajasthan | 14.82% |
| Madhya Pradesh | 9.12% |

RASonly

| | |
|---|---|
| Gujarat | 7.78% |
| Maharashtra | 6.71% |
| Other States | 45.91% |

## Dairy is a significant part of the business in Rajasthan.

### Regular Income for Farmers

- Farmers get daily income from Dairy as they sell milk.
- It decreases reliance on seasonal wages from crops.
- It provides safety to the rural households in times of agricultural insecurity due to climatic and market risks.

### Economic Security

- In Rajasthan, dairy has emerged beyond the 'supplementary occupation'.
- It serves as a financial buffer against rural poverty for rural households.
- It has helped to raise the incomes and living conditions of thousands of rural households.

### Rural Development

- Dairy activities contribute to strengthening rural employment through expansion.
- Dairy cooperatives and milk unions help the producers by enhancing their market access.
- Value addition, improved returns and job creation can result from dairy processing.

## Shift from Production to Processing

### Current Focus

- The performance of milk production in Rajasthan is already good.
- The next big challenge is to raise the processing of dairy products.
- Processing can be utilized in the production of value added dairy products and enhance the income of the farmers.

### Institutional Role

- The role of RCDF and milk unions is playing significant role in the dairy economy of Rajasthan.

RASonly

- Their combined business was almost ₹10,500 crore in 2025-26.
- A special fund of ₹2,000 crore has been sanctioned for dairy infrastructure development.

## Conclusion

The increased contribution of the dairy sector to Rajasthan's rural economy is reflected in its becoming the second largest milk-producing state in India. Dairy accounts for 14.82 per cent of the country's production and has increased in output by almost five times since 2001–02, thus contributing positively to the livelihood security of the country. Processing, infrastructure development will further consolidate farmer income and rural employment and strengthen the contribution of Rajasthan in the dairy economy of India.

## MCQs

1. According to the Basic Animal Husbandry Statistics 2025, what percentage of milk does Rajasthan contribute to the total milk production in India?

(a) 9.12 percent

(b) 14.82 percent

(c) 15.66 percent

(d) 7.78 percent

Answer: (b) 14.82 percent

Explanation : According to Basic Animal Husbandry Statistics 2025, the total milk production in India was 247.87 M tonnes. The state of Rajasthan has made 14.82 per cent of this total which is the second highest milk producing state in the country. This also indicates around 13.3% of the country's milk supply is produced by the state of Rajasthan.

2. Based on this data, which State is the largest milk producing State in India?

(a) Rajasthan

(b) Madhya Pradesh

(c) Uttar Pradesh

(d) Gujarat

Answer: (c) Uttar Pradesh

Explanation: UP accounts for the highest production of milk in India with 15.66 per cent. Rajasthan is second with 14.82 percent followed by Madhya Pradesh with 9.12

RASonly

per cent, Gujarat with 7.78 percent and Maharashtra with 6.71 per cent. Hence, according to the data, Uttar Pradesh is the largest milk-producing state.

3. After strong growth in milk production, what is the new thrust of the dairy industry in Rajasthan?

(a) Reducing milk production
(b) Increasing dairy processing
(c) Ending dairy cooperatives
(d) Replacing animal husbandry with crop farming

Answer:b) increasing dairy processing.

Explanation: Milk production in Rajasthan is already high and has increased from nearly 77 lakh tonnes in 2001-02 to more than 367 lakh tonnes in 2024-25. Increased production is now giving way to dairy processing, and the current emphasis is on the latter. This can enhance value addition, bolster dairy infrastructure and enhance farmers' income.

# राजस्थान में दुग्ध क्षेत्र और आजीविका सुरक्षा

राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बन गया है। राज्य में दुग्ध क्षेत्र किसानों के लिए आजीविका का मजबूत आधार बनकर उभरा है। फसल से आय सामान्यतः वर्ष में एक या दो बार होती है, जबकि दूध उत्पादन ग्रामीण परिवारों को नियमित आय उपलब्ध कराता है। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार, भारत का कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन रहा, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 14.82 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि देश में लगभग हर 7वां लीटर दूध राजस्थान से आता है। राज्य में दूध उत्पादन 2001-02 में लगभग 77 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 367 लाख टन तक पहुंच गया है।

## प्रमुख बिंदु

- राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बन गया है।
- भारत के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 14.82 प्रतिशत है।
- मूल पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार, भारत का कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन रहा।
- राजस्थान में दूध उत्पादन 2001-02 के लगभग 77 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 367 लाख टन हो गया।
- दुग्ध क्षेत्र ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित आय और आर्थिक सुरक्षा का स्रोत बन गया है।
- राजस्थान का दुग्ध क्षेत्र अब केवल उत्पादन पर नहीं, बल्कि प्रसंस्करण पर भी ध्यान दे रहा है।
- 2025-26 में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ और जिला दुग्ध संघों का संयुक्त कारोबार लगभग ₹10,500 करोड़ तक पहुंच गया।

RASonly

- राज्य सरकार ने दुग्ध अवसंरचना विकास के लिए ₹2,000 करोड़ के विशेष कोष को मंजूरी दी है।

## भारत के प्रमुख दूध उत्पादक राज्य

| राज्य | भारत के दूध उत्पादन में हिस्सेदारी |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 15.66% |
| राजस्थान | 14.82% |
| मध्य प्रदेश | 9.12% |
| गुजरात | 7.78% |
| महाराष्ट्र | 6.71% |
| अन्य राज्य | 45.91% |

## राजस्थान के लिए दुग्ध क्षेत्र का महत्व

### किसानों के लिए नियमित आय

- दूध की बिक्री से किसानों को दैनिक आय प्राप्त होती है।
- इससे किसानों की मौसमी फसल आय पर निर्भरता कम होती है।
- मौसम और बाजार जोखिमों से उत्पन्न कृषि अनिश्चितता के समय यह ग्रामीण परिवारों को सहारा देता है।

### आर्थिक सुरक्षा

- राजस्थान में दुग्ध व्यवसाय अब केवल सहायक व्यवसाय तक सीमित नहीं रहा है।
- यह ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रहा है।
- इससे हजारों ग्रामीण परिवारों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

### ग्रामीण विकास

- दुग्ध गतिविधियों के विस्तार से ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलती है।
- दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संघ उत्पादकों को बेहतर बाजार पहुंच उपलब्ध कराते हैं।
- दुग्ध प्रसंस्करण से मूल्य संवर्धन, बेहतर प्रतिफल और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

RASonly

# उत्पादन से प्रसंस्करण की ओर बदलाव

## वर्तमान ध्यान

- राजस्थान ने दूध उत्पादन में मजबूत वृद्धि हासिल कर ली है।
- अब अगला प्रमुख लक्ष्य दुग्ध प्रसंस्करण को बढ़ाना है।
- प्रसंस्करण से मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं और किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।

## संस्थागत भूमिका

- राजस्थान सहकारी डेयरी संघ और जिला दुग्ध संघ राजस्थान की दुग्ध अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- 2025-26 में इनका संयुक्त कारोबार लगभग ₹10,500 करोड़ रहा।
- दुग्ध अवसंरचना विकास के लिए ₹2,000 करोड़ का विशेष कोष स्वीकृत किया गया है।

## निष्कर्ष

राजस्थान का भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बनना राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दुग्ध क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। 14.82 प्रतिशत राष्ट्रीय हिस्सेदारी और 2001-02 से लगभग 5 गुना उत्पादन वृद्धि के साथ दुग्ध क्षेत्र आजीविका सुरक्षा का मजबूत आधार बन गया है। प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास पर ध्यान किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और भारत की दुग्ध अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भूमिका को और मजबूत कर सकता है।

## बहुविकल्पीय प्रश्न

**1. मूल पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है?**

(a) 9.12 प्रतिशत
(b) 14.82 प्रतिशत
(c) 15.66 प्रतिशत
(d) 7.78 प्रतिशत

**उत्तर: (b) 14.82 प्रतिशत**

**व्याख्या:** मूल पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत का कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन रहा। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 14.82 प्रतिशत है, जिससे राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बन गया है। इसका अर्थ यह भी है कि देश में उत्पादित लगभग हर 7वां लीटर दूध राजस्थान से आता है।

**2. दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन-सा है?**

(a) राजस्थान
(b) मध्य प्रदेश

RASonly

(c) उत्तर प्रदेश
(d) गुजरात

**उत्तर: (c) उत्तर प्रदेश**

**व्याख्या:** दिए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के दूध उत्पादन में 15.66 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है। राजस्थान 14.82 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश 9.12 प्रतिशत, गुजरात 7.78 प्रतिशत और महाराष्ट्र 6.71 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ आते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है।

**3. दूध उत्पादन में मजबूत वृद्धि के बाद राजस्थान के दुग्ध क्षेत्र का नया प्रमुख ध्यान किस पर है?**

(a) दूध उत्पादन कम करना
(b) दुग्ध प्रसंस्करण बढ़ाना
(c) दुग्ध सहकारी समितियों को समाप्त करना
(d) पशुपालन को फसल खेती से बदलना

**उत्तर: (b) दुग्ध प्रसंस्करण बढ़ाना**

**व्याख्या:** राजस्थान ने दूध उत्पादन में मजबूत वृद्धि हासिल की है। राज्य का दूध उत्पादन 2001-02 में लगभग 77 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 367 लाख टन हो गया है। अब ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने से आगे बढ़कर दुग्ध प्रसंस्करण पर केंद्रित हो रहा है। इससे मूल्य संवर्धन, दुग्ध अवसंरचना और किसानों की आय को मजबूती मिल सकती है।

RASonly

# Thar Dry Port and Rajasthan's Logistics Development

# THAR DRY PORT AND RAJASTHAN'S LOGISTICS DEVELOPMENT

The Thar Dry port has been launched at Hirnoda in Phulera, which is a great step towards Rajasthan becoming a leading logistics hub of the north India. This is an integrated multimodal logistics park developed under the project Rising Rajasthan and the PM Gati Shakti Mission under the Central Government with a focus on connecting the trade of Rajasthan with seaports. Container, steel, cement and warehousing activities are expected to be conducted at the port. It will also benefit to the exporters by reducing the transportation cost, saving time, and facilitating them to access the major ports of Gujarat like Mundra, Pipavav, and Kandla.

## Key Highlights

- Thar dry port has been inaugurated at Hirnoda, Phulera.
- It has been created as per Rising Rajasthan and PM Gati Shakti Mission.
- The project is an integrated multimodal logistics park.
- It is spread over more than 100 acres.
- It is just approximately 55 kilometres away from Jaipur.
- The port is directly linked to the Western DEDF.
- It will tie up with industrial centers like Bichun, Bagru, Dudu and Sitapura to Gujarat's ports.
- It will assist various sectors like container trade, steel sector, cement, warehousing and exports.

## Strategic Importance of Thar Dry Port

### Link with Western Dedicated Freight Corridor

- The dry port is directly linked to Western Dedicated Freight Corridor.
- This will enhance freight movement from Rajasthan to major seaports.

- It will establish a seamless pathway for the goods traffic to and from Mundra, Pipavav and Kandla ports.
- Allow the port to lessen reliance on long road transportation.

### Advantage for Jaipur and Nearby Areas

- This will be a dry port for the city of Jaipur and the surrounding industrial region.
- Products such as handicrafts, garments and marble can be transported more efficiently.
- Exporters will be able to transport goods using rail-based container facilities.
- This will enhance the competitiveness of Rajasthan in the domestic and international trade.

### Benefits for Rajasthan

Cheaper and quicker.Less expensive and faster.

- A long journey of almost 700 kilometres can be avoided by exporters.
- Logistics costs can be reduced using rail.
- Faster transport will help businesses deliver faster.
- Improved logistics will make Rajasthan more investment-friendly.

### The new investment in the industry and employment is considerable.

- Well-developed logistics systems are able to lure domestic and foreign firms.
- Rajasthan could also be better suited for manufacturing units, owing to better freight connectivity.
- More than 5000 jobs will be generated as a result of the project, both direct and indirect.
- It can help fulfill the vision of Rajasthan becoming an important industrial and logistics hub.

### Role in Economic Transformation

The Thar Dry Port is an example of how a barren land can be made a business opportunity and logistics hub. Rajasthan lacks a seacoast but has a great advantage of land, minerals, industrial areas and a central location. Rajasthan, with its multimodal connectivity and port-linked infrastructure, can play a greater role in the supply chain for North India and become a preferred logistics hub for North India.

## Objectives and Benefits

### Objectives

- Enhance logistics and freight connectivity in Rajasthan.
- Connect industrial areas to seaports.
- Minimise transport costs and travel time for exporters.

RASonly

- Improve multi-modal trade facilitation.
- Encourage industries to grow by improving logistical support.

### Benefits

- Provides support to exporters of Jaipur & its surrounding areas.
- Offers less pressure on road transport.
- Promotes investment in manufacturing and warehousing.
- Creates employment opportunities.
- Enhances the logistics infrastructure position of Rajasthan as a Logistics Hub of North India.

## Conclusion

The Dry Port at Hirnoda is a big contribution to Rajasthan's infrastructure-driven economic growth. The project will connect industrial hubs to the Western DFC and Gujarat's ports, which will cut logistics costs and boost the efficiency of exports, and attract new industries. It has the potential to be a relevant factor in establishing Rajasthan as a key logistics and industrial centre in North India.

## MCQs

o In which district of Rajasthan is Thar Dry Port launched?

(a) Sitapura, Jaipur

(b) Hirnoda, Phulera

(c) Bagru, Jaipur

(d) Dudu, Rajasthan

Answer: (b) Hirnoda, Phulera

Explanation : The Thar Dry Port has been opened at Hirnoda, Phulera. It has been built as an integrated multimodal logistics park under the PM Gati Shakti Mission, under the aegis of Rising Rajasthan and the Central Government. It is also located in close proximity to the city of Jaipur and its strategic position and linkages with key freight corridors to support Rajasthan's logistics development.

o Which major freight corridor is directly connected with to Thar Dry Port?

a) Eastern Dedicated Freight Corridor
(b) Western Dedicated Freight Corridor
(c) North-South Freight Corridor
(d) East-West Industrial Corridor

Answer : (b) Western Dedicated Freight Corridor

RASonly

Explanation : The Thar Dry Port is in direct connectivity with the Western Dedicated Freight Corridor. This connectivity shall facilitate the connectivity of various industrial hubs like Bichun, Bagru, Dudu and Sitapura with the major ports of Gujarat like Mundra and Pipavav. It will positively impact the transportation of freight, logistics costs and export-oriented industries in Rajasthan.

3. One main expected advantage for exporters to benefit from the Thar Dry Port is?

(a) It will derail the railway transport system.

(b) It will make the road trip to 700km longer.

(c) It will cut down on logistics expenses and time.

(d) It will cut out Rajasthan from seaports.

Answer: (c) it will cut down logistics expenses and save time.

Explanation: The Thar Dry Port will help in the reduction of logistics cost and save time for the exporters by facilitating better freight connectivity by rail movement. The exporters of Jaipur and its surrounding areas will be able to export their products fast to the ports like Pipavav, Mundra and Kandla and it will also eliminate the need to spend long hours travelling by road.

## थार शुष्क बंदरगाह और राजस्थान में रसद प्रबंधन विकास

फुलेरा के हिरनोदा में थार शुष्क बंदरगाह की शुरुआत राजस्थान को उत्तर भारत का प्रमुख रसद केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना उदीयमान राजस्थान और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान के तहत विकसित की गई है। यह एक एकीकृत बहु-माध्यमीय रसद उद्यान है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के व्यापार को सीधे समुद्री बंदरगाहों से जोड़ना है। इस बंदरगाह से माल डिब्बा व्यापार, इस्पात, सीमेंट, भंडारण और निर्यात से जुड़े कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। इससे निर्यातकों को परिवहन लागत कम करने, समय बचाने और गुजरात के मुंद्रा, पीपावाव तथा कांडला जैसे प्रमुख बंदरगाहों तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

### प्रमुख बिंदु

- थार शुष्क बंदरगाह फुलेरा के हिरनोदा में शुरू किया गया है।
- यह परियोजना उदीयमान राजस्थान और प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान के तहत विकसित की गई है।
- यह एक एकीकृत बहु-माध्यमी रसद उद्यान है।
- यह 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- यह बंदरगाह सीधे पश्चिमी समर्पित माल गलियारे से जुड़ा हुआ है।

RASonly

- यह बिचून, बगरू, दूदू और सीतापुरा जैसे औद्योगिक केंद्रों को गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ेगा।
- यह माल डिब्बा व्यापार, इस्पात, सीमेंट, भंडारण और निर्यात जैसे क्षेत्रों को सहायता देगा।

## थार शुष्क बंदरगाह का सामरिक महत्व

### पश्चिमी समर्पित माल गलियारे से संपर्क

- यह शुष्क बंदरगाह सीधे पश्चिमी समर्पित माल गलियारे से जुड़ा हुआ है।
- इससे राजस्थान से प्रमुख समुद्री बंदरगाहों तक माल परिवहन में सुधार होगा।
- यह मुंद्रा, पीपावाव और कांडला बंदरगाहों की ओर जाने वाले माल के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध कराएगा।
- इससे लंबे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम हो सकती है।

### जयपुर और आसपास के क्षेत्रों को लाभ

- जयपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को इस शुष्क बंदरगाह से लाभ मिलेगा।
- हस्तशिल्प, परिधान और संगमरमर जैसे उत्पादों का परिवहन अधिक कुशलता से किया जा सकेगा।
- निर्यातक रेल आधारित माल डिब्बा सुविधा के माध्यम से सामान भेज सकेंगे।
- इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में राजस्थान की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।

## राजस्थान के लिए लाभ

### कम लागत और तेज परिवहन

- निर्यातक लगभग 700 किलोमीटर की लंबी सड़क यात्रा से बच सकेंगे।
- रेल आधारित माल परिवहन से रसद लागत कम हो सकती है।
- तेज परिवहन से व्यवसायों की आपूर्ति दक्षता बढ़ेगी।
- बेहतर रसद व्यवस्था राजस्थान को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाएगी।

### उद्योग और रोजगार को बढ़ावा

- मजबूत रसद अवसंरचना घरेलू और विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सकती है।
- बेहतर माल परिवहन संपर्क के कारण राजस्थान की विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिक उपयुक्त बन सकता है।
- इस परियोजना से 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है।
- यह राजस्थान को प्रमुख औद्योगिक और रसद केंद्र बनाने के व्यापक लक्ष्य को समर्थन दे सकता है।

RASonly

## आर्थिक परिवर्तन में भूमिका

थार शुष्क बंदरगाह यह दर्शाता है कि बंजर या कम उपयोग वाली भूमि को व्यापार और रसद अवसर में बदला जा सकता है। राजस्थान के पास समुद्री तट नहीं है, फिर भी राज्य को भूमि उपलब्धता, खनिज संपदा, औद्योगिक क्षेत्रों और केंद्रीय स्थिति जैसे मजबूत लाभ प्राप्त हैं। बहु-माध्यमीय संपर्क और बंदरगाह आधारित अवसंरचना के माध्यम से राजस्थान उत्तर भारत की आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है और उत्तर भारत का पसंदीदा रसद केंद्र बन सकता है।

## उद्देश्य और लाभ

### उद्देश्य

- राजस्थान में रसद और माल परिवहन संपर्क को बेहतर बनाना।
- अंतर्देशीय औद्योगिक क्षेत्रों को समुद्री बंदरगाहों से जोड़ना।
- निर्यातकों की परिवहन लागत और यात्रा समय को कम करना।
- बहु-माध्यमीय व्यापार अवसंरचना को मजबूत करना।
- बेहतर रसद सहायता के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

### लाभ

- जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के निर्यातकों को सहायता मिलती है।
- सड़क परिवहन पर दबाव कम होता है।
- विनिर्माण और भंडारण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
- रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
- उत्तर भारत के रसद केंद्र के रूप में राजस्थान की स्थिति मजबूत होती है।

## निष्कर्ष

हिरनोदा में थार शुष्क बंदरगाह की शुरुआत राजस्थान के अवसंरचना आधारित आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना औद्योगिक क्षेत्रों को पश्चिमी समर्पित माल गलियारे और गुजरात के बंदरगाहों से जोड़कर रसद लागत को कम कर सकती है, निर्यात दक्षता बढ़ा सकती है और नए उद्योगों को आकर्षित कर सकती है। यह राजस्थान को उत्तर भारत का मजबूत रसद और औद्योगिक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

## बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान में थार शुष्क बंदरगाह कहां शुरू किया गया है?

(a) सीतापुरा, जयपुर
(b) हिरनोदा, फुलेरा
(c) बगरू, जयपुर
(d) दूदू, राजस्थान

उत्तर: (b) हिरनोदा, फुलेरा

RASonly

व्याख्या: थार शुष्क बंदरगाह फुलेरा के हिरनोदा में शुरू किया गया है। इसे उदीयमान राजस्थान और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान के तहत एक एकीकृत बहु-माध्यमीय रसद उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। जयपुर के पास इसकी स्थिति और प्रमुख माल गलियारों से इसका संपर्क राजस्थान के रसद विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

2. थार शुष्क बंदरगाह किस प्रमुख माल गलियारे से सीधे जुड़ा हुआ है?

(a) पूर्वी समर्पित माल गलियारा
(b) पश्चिमी समर्पित माल गलियारा
(c) उत्तर-दक्षिण माल गलियारा
(d) पूर्व-पश्चिम औद्योगिक गलियारा

उत्तर: (b) पश्चिमी समर्पित माल गलियारा

व्याख्या: थार शुष्क बंदरगाह सीधे पश्चिमी समर्पित माल गलियारे से जुड़ा हुआ है। यह संपर्क बिचून, बगरू, दूदू और सीतापुरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को मुंद्रा और पीपावाव जैसे गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ने में सहायता करेगा। इससे माल परिवहन में सुधार, रसद लागत में कमी और राजस्थान के निर्यातोन्मुख उद्योगों को समर्थन मिलेगा।

3. निर्यातकों के लिए थार शुष्क बंदरगाह का एक प्रमुख अपेक्षित लाभ क्या है?

(a) यह रेल आधारित परिवहन को रोक देगा।
(b) यह 700 किलोमीटर की सड़क यात्रा को और लंबा करेगा।
(c) यह रसद लागत कम करेगा और समय बचाएगा।
(d) यह राजस्थान को समुद्री बंदरगाहों से अलग कर देगा।

उत्तर: (c) यह रसद लागत कम करेगा और समय बचाएगा।

व्याख्या: थार शुष्क बंदरगाह बेहतर रेल आधारित माल परिवहन संपर्क उपलब्ध कराकर निर्यातकों की रसद लागत कम करने और समय बचाने में सहायक होगा। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के निर्यातक अपने उत्पादों को मुंद्रा, पीपावाव और कांडला जैसे बंदरगाहों तक अधिक कुशलता से भेज सकेंगे। इससे लंबी सड़क यात्राओं पर निर्भरता भी कम होगी।

RASonly